(d) how much further delay is envisaged in completion of the projects and what will be the further revised estimates in respect thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) Irrigation and Flood Control is in the State List of the Constitution and as such the concerned State is primarily responsible for investigation, formulation, Planning, execution, financing and management of irrigation projects. The funding priority for irrigation projects is to be determined by the State Governments themselves within their available resources in the Annual Plans. As of now, 52 approved major and medium irrigation projects are under various stages of construction in the State of Maharashtra. The approved outlay under major and medium irrigation sector for 1993-94 was Rs. 568.23 crores whereas the revised approved outlay was Rs. 596.37 crores.

उत्तर प्रदेश से पिछड़ेपन का हटाया जाना

6349. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने का विचार रखता है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का आवंटन संबंधी फार्मूला उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बन रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के साथ हाल ही में कोई बात हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारतीय आयोजना का प्रमुख लक्ष्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों में विकास कार्यक्रमों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन के माध्यम से इसे प्राप्त करना है।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत जनसंख्या तथा आय मानदंड (अर्थात् राष्ट्रीय औसत से नीचे राज्य की प्रति व्यक्ति आय) के आधा पर यथा केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध कराने वाला यह फार्मूला उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को उचित महत्व देता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) हाल ही में इस विषय पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हुई है । यद्यपि राज्य की वार्षिक योजना (1994–95) प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी–फरवरी, 1994 में विचार विमर्श हुआ था ।

Recommendation of Krishnaswamy Committee Report

6350. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether a Conference of Voluntary Organisations was held in March, 1994 which made certain suggestions and recommendations to government for their smooth functioning;

(b) if so, what are their main recommendations and reaction of government thereto;

(c) whether government have since formulated some policy for the Voluntary Sector if so, details thereof; and